

स्वराज इंडिया

दैनिक सांध्यकालीन

» Pg12

खेलों में
अच्छा प्रदर्शन
करने वालों
को सरकार
देगी नौकरी

कानपुर, गुरुवार, 09 अक्टूबर, 2025

वर्ष: 02, अंक: 266, पृष्ठ: 8+4, मूल्य: ₹ 2/-

इनसाइड

...तो क्या बारूद के ढेर पर बैठा है कानपुर नगर... » Pg02

लखनऊ में बसपा का बड़ा शक्ति प्रदर्शन

गरजीं माया...! अखिलेश

पर गरम, योगी पर नरम

सड़कों पर उतरा नीला सैलाब, अपनी नेता को देखने-सुनने को बेताब दिखी भीड़, पुराने तेवरों में दिखीं बसपा सुप्रीमो



2027 विधानसभा चुनाव को लेकर फूँका बिगुल

मायावती ने कहा- इस रैली ने पहले सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे लगता है कि 2027 में यूपी में एक बार फिर पूर्ण बहुमत से सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की सोच वाली सरकार बनेगी। उन्होंने वादा किया कि वह कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लोगों को अपनी रोजी-रोटी के लिए पलायन नहीं करना पड़ेगा। **कहा-** इस रैली में अन्य दलों की तरह पैसे देकर लोग नहीं बुलाए गए हैं।

» वरिष्ठ संपादक, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

बसपा संस्थापक कांशीराम की पुण्य तिथि के अवसर पर पार्टी प्रमुख मायावती ने लखनऊ में बड़ी रैली की। ये रैली लखनऊ के कांशीराम स्मारक में हुई। मायावती करीब तीन घंटे तक मंच पर मौजूद रहीं। रैली को लेकर लखनऊ पूरी तरह नीले रंग में रंगा नजर आया। कांशीराम स्मारक स्थल पर विशाल मंच तैयार किया गया था। रामबाई अंबेडकर मैदान में बसपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के ठहरने की व्यवस्था थी। रैली में प्रदेशभर से लाखों कार्यकर्ताओं पहुंचे थे। बसपा संगठन ने करीब पांच लाख लोगों के जुटान का दावा किया है। सुरक्षा के लिए दो हजार से अधिक पुलिसकर्मी तैनात रहे, जबकि ट्रैफिक पुलिस ने वैकल्पिक मार्ग भी निर्धारित किए थे। यह रैली केवल श्रद्धांजलि कार्यक्रम नहीं, बल्कि राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखी गई।

भीड़ देखकर थर्राए विरोधी

बसपा सुप्रीमो मायावती की यह रैली और उसमें उमड़ी भीड़ देखकर बीजेपी, सपा समेत तमाम राजनीतिक दल हैरान बताए जा रहे हैं। कार्यक्रम में आये बसपा कार्यकर्ताओं और मायावती के समर्थकों का कहना है कि अब मायावती को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। 2027 में 90 फीसदी सीट बीएसपी की आने जा रही है।

लखनऊ में महारैली को संबोधित करते हुए मायावती ने बीजेपी, कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा। रैली में मायावती ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बसपा 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। मायावती ने कहा कि गठबंधन करने से हमेशा ही उनकी पार्टी को नुकसान हुआ है। हमारा वोट तो ट्रांसफर हो जाता है लेकिन दूसरी पार्टी हमें वोट ट्रांसफर नहीं होता। हमारा वोट प्रतिशत कम होता है। गठबंधन में सरकार बनती है तो ज्यादा दिन नहीं चल पाती है। एक बार कांग्रेस, एक बार सपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा 67 ही सीट जीत पाये। अकेले हमने 2007 में बहुमत की सरकार बनाई।

बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी और मान्यवर कांशीराम के आदर-सम्मान में यह स्मारक स्थल बनाया गया था तो उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम लोग यहां आने वालों से टिकट लेंगे। जिसका पैसा

लखनऊ में बनाए गए स्मारक और पार्कों के रख-रखाव में इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन दुख की बात यह है कि वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहां सपा की सरकार थी तो सपा सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबाकर रखा... हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी।

मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखित चिट्ठी के जरिए कहा और आग्रह किया कि टिकटों के पैसे को रखरखाव पर लगाया जाए। उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लेकर हमसे वादा किया कि जो भी पैसा टिकटों के जरिए आता है वह इन स्थलों के रखरखाव के लिए लगाया जाएगा। मायावती ने कहा कि मैं राज्य सरकार की आभारी हूँ कि कांशीराम स्मारक की मरम्मत कराई। टिकट के पैसे अपने पास नहीं रखा। टिकट के पैसे से मरम्मत कराई।

अखिलेश से पूछे तीखे सवाल

मायावती ने कहा कि मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहती हूँ कि जब उनकी सरकार

थी तो कांशीराम के नाम पर नगर, यूनिवर्सिटी के नाम क्यों बदले? सत्ता में नहीं रहते हैं तो महापुरुष और पीडीए याद आता है। कांशीराम स्मारक की मरम्मत नहीं होने के वजह से यहां पुष्प नहीं अर्पित नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब मरम्मत हो गई। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी राजनीति के स्वार्थ में पीडीए की बात करके लोगों को गुमराह कर रही है। जब

आजम खान से मुलाकात की खबरों का किया खंडन

आजम खान का नाम लिए बिना मायावती ने कहा कि पिछले महीने से अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरे दल से फलाना बसपा में आ रहे हैं और दिल्ली लखनऊ में मायावती से मिले हैं। मैं तो किसी से नहीं मिली मैं छुप कर किसी से नहीं मिलती।

सपा सरकार थी तो आरक्षण में पक्षपात किया। सपा सरकार ने माफिया गुंडों को बढ़ावा दिया, कानून व्यवस्था खराब कर दी।

कांग्रेस पर भी साधा निशाना

मायावती ने बीजेपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कही कि बीजेपी सरकार में भी वही स्थिति है। यूपी में कांग्रेस की सरकारों ने दलितों के लिए कुछ नहीं किया। अब इनके संविधान को हाथ में लेकर नाटक करते रहते हैं। कांग्रेस ने कभी भी बाबा साहब अंबेडकर और कांशीराम को सम्मान नहीं दिया।

बीजेपी पर दलितों से झूठे वादे करने का लगाया आरोप

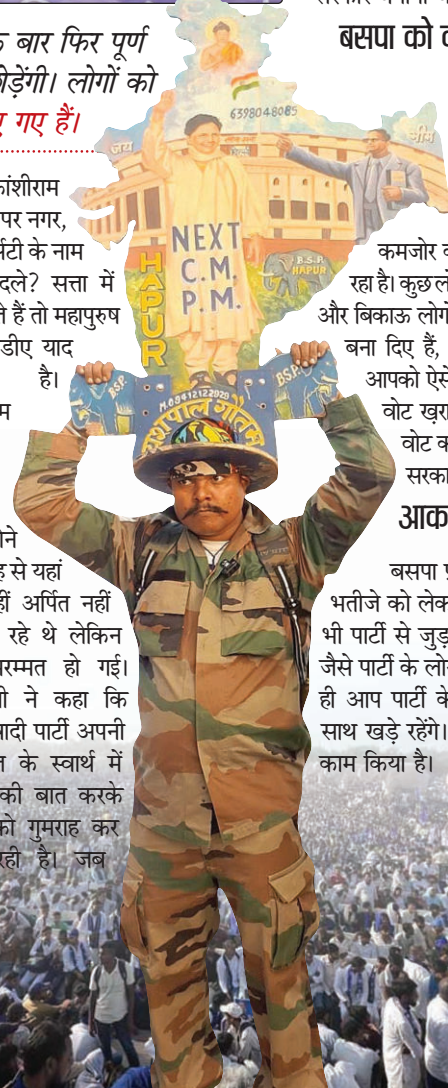
मायावती ने कहा कि बीजेपी सरकार भी दलितों के लिए झूठे वादे करती है। इसलिए बसपा को मजबूत बनाकर केंद्र और प्रदेश में सत्ता में वापस लाए। दूसरे राज्यों में जहां चुनाव है वहां भी बसपा को मजबूत कीजिए। यूपी में तो फिर से बसपा की बहुमत की सरकार बनाना बहुत जरूरी है।

बसपा को कमजोर करने की हो रही साजिश

बसपा प्रमुख ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में भी बसपा को मजबूत करें। अब पूरे देश में बसपा को कमजोर करने के लिए नया षड्यंत्र हो रहा है। कुछ लोगों ने दलित समाज से स्वार्थी और बिकाऊ लोगों का इस्तेमाल करके संगठन बना दिए हैं, जिससे बसपा कमजोर हो। आपको ऐसे लोगों को वोट देकर अपना वोट खराब नहीं करना है। बसपा को वोट करें जिससे यूपी में बसपा फिर सरकार बना सके।

आकाश आनंद की तारीफ

बसपा प्रमुख ने मायावती ने अपने भतीजे को लेकर कहा कि आकाश आनंद भी पार्टी से जुड़ गए हैं। ये अच्छी बात है। जैसे पार्टी के लोग मेरे साथ खड़े रहे हैं। वैसे ही आप पार्टी के लोग आकाश आनंद के साथ खड़े रहेंगे। आनंद कुमार ने भी बहुत काम किया है।



...तो क्या बारूद के ढेर पर बैठा कानपुर नगर

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। दीपावली से कई दिन पहले ही कानपुर नगर बारूद के ढेर में तब्दील हो चुका है। प्रशासन की रोक के बावजूद व्यापारी त्योहार के अंतिम दिनों में दाम बढ़ने की आशंका के चलते 20 दिन पहले ही आगरा, मैनपुरी, हाथरस और वाराणसी से भारी मात्रा में पटाखे मंगवा लेते हैं। नवाबगंज से लेकर मेस्टन रोड, दबौली, गोविंद नगर, शास्त्री नगर और बर्बा तक की गलियों में करोड़ों रुपये के पटाखों का अवैध भंडारण हो रहा है, लेकिन थाना पुलिस ने आंखें मूंद रखी हैं।

बुधवार शाम मेस्टन रोड के मिश्री बाजार में हुआ विस्फोट इसी लापरवाही की जीती-जागती मिसाल है। अगर पुलिस समय रहते सतर्क होती, तो यह हादसा टल सकता था। शहर में बिटूर, फूलबाग, किदवई नगर, बर्बा और नौबस्ता समेत 42 स्थानों पर करीब एक हजार फुटकर दुकानों और 20



» अवैध पटाखों के भंडारण पर रोक के बावजूद गलियों में चल रहा धड़ले से कारोबार

» मेस्टन रोड के मिश्री बाजार में विस्फोट ने उजागर की पुलिस की बड़ी लापरवाही

थोक कारोबारियों के जरिए पटाखों की बिक्री होती है। सूत्रों के मुताबिक, दीपावली से 20 दिन पहले ही शहर में



कानपुर- पुलिस कमिश्नर ने मूलगंज थाने के एसएचओ सहित 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। इसके पीछे बताया जा रहा है कि अवैध पटाखा का कारोबार चल रहा था लेकिन चौकी में तैनात पुलिस कर्मियों ने कोई एक्शन नहीं लिया।

पांच करोड़ से ज्यादा के पटाखे पहुंच चुके हैं। कई व्यापारी सजावटी दुकानों की आड़ में देशी पटाखों का गुप्त कारोबार कर रहे हैं, जिससे पूरा शहर



बारूद के ढेर पर बैठा है।

पुलिस-नेता गटजोड़ ने बनाया 'बारूद सिंडीकेट'

मेस्टन रोड पर अवैध पटाखा बाजार का सिंडीकेट वर्षों से सक्रिय है। इस बार भी करीब 15 दिन पहले से ही बाजार सज गया, और पुलिस ने अनदेखी की। सूत्र बताते हैं कि मूलगंज पुलिस और कोतवाली थाने की मिलीभगत से रोजाना लाखों की वसूली हो रही थी। बुधवार के विस्फोट के बाद जब एलआईयू, बम निरोधक दस्ता और डोंग स्कूड ने मौके पर जांच शुरू की, तो कई दुकानों में पटाखों के पैकेट, सीको ब्रांड के बॉक्स और छिपे त्रिपालों के नीचे

भारी बारूद का जखीरा मिला।

कई दुकानदार शटर गिराकर भागे

जांच के दौरान अधिकांश दुकानदारों ने पटाखों की बिक्री से इंकार किया और शटर गिराकर भाग निकले। सूत्रों के अनुसार, इस अवैध कारोबार में कुछ पुलिस अधिकारी और सत्ताधारी दल से जुड़े नेता भी शामिल हैं, जो हर साल थोक पटाखा बाजार पर रोक लगवाकर इस भूमिगत व्यापार को बढ़ावा देते हैं। दीपावली नजदीक है, लेकिन प्रशासन अब तक कार्रवाई करने से बच रहा है जिससे साफ है कि कानपुर में दीपावली रोशनी से ज्यादा खतरे की चेतावनी बनती जा रही है।

मेस्टन रोड ब्लॉस्ट 70 प्रतिशत जले चार लोग, मांस के उड़े चीथड़े



» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। मूलगंज थाना क्षेत्र के बिसातखाना में बुधवार शाम करीब 7-30 बजे दुकानों के बाहर खड़ी दो स्कूटी में तेज धमाके हुए। धमाके इतने जोरदार थे कि 500 मीटर दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी। ब्लॉस्ट में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों के चीथड़े उड़ गए। धमाका इतना तेज था कि पास खड़ी सुहाना (16) के चेहरे और पैर के मांस के टुकड़े शरीर से अलग हो गए। गंभीर घायलों को उर्सला ले जाया गया। गंभीर हालत देख डॉक्टरों ने तुरंत केजीएमयू के लिए रेफर कर दिया। गंभीर घायलों में सुहाना के अलावा अश्विनी कुमार (54), अब्दुल मुत्तलिब (24) और रईसुद्दीन (40) शामिल हैं। अस्पताल के सर्जन डॉ. बीके सिंह ने दो रोगियों मो. मुर्सलीन (25) और जुबीन (15) को भर्ती कर लिया। करीब 30 से 60 फीसदी तक जले दोनों का इलाज उर्सला में चल रहा है। डॉ. बीके सिंह ने बताया कि गंभीर घायल 70 फीसदी या उससे ज्यादा जल गए। ब्लॉस्ट में जो करीब था उसके चीथड़े से उड़े हुए हैं। युवती की हालत काफी खराब थी। सभी को केजीएमयू रेफर किया है। दो रोगियों को यहीं पर भर्ती कर इलाज कर रहे हैं। बाकी दो मामूली घायल हुए थे उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया है।

मेस्टन रोड ब्लास्ट: रातभर चला सर्व ऑपरेशन

12 दुकानदार हिरासत में, कई दुकानों में मिला अवैध पटाखों का जखीरा

» प्रमुख संवाददाता स्वराज इंडिया

कानपुर। मेस्टन रोड के मिश्री बाजार में बुधवार शाम हुए भीषण विस्फोट के बाद पुलिस प्रशासन ने गुरुवार सुबह बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस आयुक्त के निर्देश पर संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) ने एसीपी कोतवाली आशुतोष कुमार को हटा दिया है। वहीं, मूलगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह, चौकी प्रभारी एसआई रोहित तोमर, जेबरा मोबाइल कांस्टेबल चेतन कुमार, अमित कुमार, बीट कांस्टेबल ब्रह्मानंद और हेड कांस्टेबल इमामुल हक को निलंबित कर दिया गया है।

यह कार्रवाई अवैध पटाखों के भंडारण पर लापरवाही के चलते की गई है। बुधवार शाम मरकज मस्जिद से करीब 100 मीटर दूर खड़ी एक चोरी की स्कूटी में हुए विस्फोट ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था। धमाके की चपेट में महिला समेत 12 लोग घायल हुए, जिनमें से आठ को उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया। विस्फोट इतना भीषण था कि आसपास के घरों की खिड़कियां टूट गईं और दीवारों में दरारें पड़ गईं। पांच मिनट तक धुंध और बारूद की गंध से पूरा इलाका ढका रहा।

» साजिश, हादसा या शरारत

घटना के बाद एटीएस और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। देर रात तक चले सर्व ऑपरेशन में पुलिस ने मिश्री बाजार और आसपास के इलाकों से 12 दुकानदारों को हिरासत में लिया।

जांच में कई दुकानों में अवैध पटाखों का भंडारण मिला, जिसके बाद पुलिस ने इनके



» पुलिस कमिश्नर की बड़ी कार्रवाई एसीपी कोतवाली आशुतोष कुमार को हटाया, छह पुलिसकर्मी निलंबित

» महिला समेत 12 लोग घायल, एटीएस और पुलिस टीमों ने कई घंटे की जांच के बाद एफआईआर दर्ज करने की तैयारी

खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी शुरू की है। हिरासत में लिए गए लोगों में मिश्री बाजार

निवासी फराज, फैजान सिद्दीकी, मछली टोला के शादाब, हसन वारसी, मूलगंज के कमाल खां का हाता निवासी फैजान, बिसाली बाजार निवासी मो. तारीक, प्रेमनगर निवासी हाजी प्रवेश व उसका बेटा अजहर, मेस्टन रोड के हेमंत पांडेय, नौशाल अहमद, मो. मोहज्जम और फरदीन शामिल हैं।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह विस्फोट किसी साजिश, हादसे या शरारत का परिणाम था, इसकी जांच एटीएस समेत कई एजेंसियां कर रही हैं।

फिलहाल, कमिश्नरट पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई करते हुए यह संदेश दे दिया है कि सुरक्षा में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नगर आयुक्त सुधीर कुमार का तबादला

» एयर क्वालिटी से लेकर

स्वच्छता रैंकिंग तक, कानपुर को दिलाई नई पहचान — डेढ़ साल में दिखाया ईमानदार कार्यशैली का असर

» स्वराज इंडिया ब्यूरो,

कानपुर। कानपुर नगर आयुक्त सुधीर कुमार का बुधवार देर शाम अचानक तबादला कर दिया गया। शासन ने आदेश जारी कर उन्हें विशेष सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग तथा अपर महानिरीक्षक निबंधन बनाया है। उनकी जगह रायबरेली के मुख्य विकास अधिकारी अर्पित उपाध्याय को नया नगर आयुक्त नियुक्त किया गया है।

इस अप्रत्याशित बदलाव से शहर में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। नगर निगम सदन में जिस दिन उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उस दिन किसी पार्षद या प्रतिनिधि ने उनके प्रति नाराजगी नहीं जताई थी। बावजूद इसके डेढ़ साल का कार्यकाल पूरा होने से पहले उनका तबादला सभी को चौंकाने वाला रहा।

नगर आयुक्त के तबादले की खबर मिलते ही शहरवासियों में निराशा का माहौल देखा गया।



कई नागरिकों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा - सुधीर कुमार जैसे अधिकारी ही शहर को बदल सकते हैं, उनका जाना कानपुर के लिए नुकसान है।

नगर निगम कर्मचारियों ने भी कहा कि उनकी कार्यशैली पारदर्शी थी और वह शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करते थे। उनके शुरू किए गए जनसुनवाई शुरुवार और ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली को जनता ने खूब सराहा था।

वरिष्ठ पार्षद पप्पू पांडेय, सौहेल अहमद, अर्पित यादव, लक्ष्मी कोरी, राज किशोर यादव, कुंती राम विलास निषाद और नीरज कुरील, नीरज मिश्रा, लियाकत अली सहित अन्य पार्षदों ने कहा कि सुधीर कुमार ने

शहरवासी बोले - ऐसे अधिकारी बार-बार नहीं मिलते

अपने अल्प कार्यकाल में यह साबित किया कि ईमानदारी और संकल्प के साथ यदि प्रशासन काम करे, तो बदनाम शहर भी नई पहचान बना सकता है। उनका कार्यकाल कानपुर की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए एक मिसाल रहेगा। पवन गुप्ता ने कहा कि सुधीर कुमार का कार्यकाल ऐतिहासिक रहा।

स्वच्छता और हरियाली के प्रतीक बने सुधीर कुमार

सुधीर कुमार ने जुलाई 2024 में नगर आयुक्त का पद संभाला था।

उनके नेतृत्व में कानपुर नगर निगम ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। क्लीन कानपुर-ग्रीन कानपुर मुहिम के तहत उन्होंने न सिर्फ सफाई व्यवस्था सुधारी, बल्कि शहर को प्रदूषण मुक्त करने के लिए भी कई कदम उठाए। उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा संग्रह और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार सहित वेस्ट टू वंडर पार्क और वेस्ट टू आर्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत करवाई। हरित पट्टी विस्तार और पौधारोपण के विशेष अभियान चलाए। एक नागरिक-एक पौधा और जन संवाद मंच जैसे जनसहभागिता कार्यक्रम आगे बढ़ाए। नालों की सफाई और सीवेज ट्रीटमेंट व्यवस्था को गति देने में कई कार्य किए। इन अभियानों का असर यह रहा कि कानपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगातार बेहतर हुआ और शहर ने प्रदूषित शहरों की सूची से दूरी बनाई।

अब जिम्मेदारी अर्पित उपाध्याय के कंधों पर



नवागंतुक नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय

नई जिम्मेदारी संभालने जा रहे अर्पित उपाध्याय के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी - सुधीर कुमार की गति को बनाए रखना। कानपुर को हरित, स्वच्छ और स्मार्ट सिटी बनाने की जो दिशा पिछले डेढ़ साल में बनी, उस पर अब उन्हें आगे बढ़ना होगा। सीएम ग्रिड योजना, फ्लड प्लान, पार्कों का सौंदर्यीकरण सहित अन्य बड़ी योजनाओं पर ध्यान देना होगा।

अचानक तबादले के पीछे क्या है वजह?

सूत्रों के मुताबिक, हाल ही में नगर निगम द्वारा चुन्नीगंज स्थित नए कन्वेंशन सेंटर को बिना औपचारिक उद्घाटन के एक सामाजिक संस्था को आयोजन के लिए उपलब्ध कराया गया था।

बताया जा रहा है कि इस निर्णय से शासन स्तर पर असहमति हुई और यही तबादले की एक संभावित वजह मानी जा रही है। हालांकि, शासन की ओर से इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि कारण और भी हो सकते हैं लेकिन ठोस जानकारी नहीं मिली है।

अच्छा काम करने वाले अफसर, राजनीति के भेंट चढ़ जाते हैं

» रवीना त्यागी का उदाहरण याद दिलाता है कानपुर की सड़कों की सच्चाई

» स्वराज इंडिया ब्यूरो,

कानपुर में यह पुराना सवाल बार-बार उभरता है - क्या ईमानदार अफसरों को शहर सुधारने का मौका मिलता है, या वे राजनीतिक दबावों के चलते जल्दी ही हट जाते हैं? इस संदर्भ में कई लोग डूबकर रवीना त्यागी को याद करते हैं। उनका तबादला कुछ समय पहले ही हुआ था, लेकिन उनके कार्यकाल में किए गए ट्रैफिक सुधार आज भी शहरवासियों की



स्मृति में ताजा हैं। कल्याणपुर क्रॉसिंग पर वन-वे

सिस्टम लागू कर जाम कम किया। किदवाई नगर से टाटमिल पुल तक डिवाइडर लगवाकर वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित की। जरीब चौकी, टाटमिल, घंटाघर जैसे व्यस्त चौराहों पर ट्रैफिक अनुशासन में सुधार किया। उनके इन प्रयासों से स्पष्ट था कि अगर रवीना त्यागी को समय मिलता, तो कानपुर की ट्रैफिक व्यवस्था एक नए दौर में पहुँच सकती थी। लेकिन अफसोस, राजनीतिक दबाव और व्यापारिक हितों के चलते उनका तबादला कर दिया गया। और जो अधिकारी उनके बाद आए, उन्होंने न तो बनाए गए सिस्टम को आगे बढ़ाया, न शहर की ट्रैफिक समस्या में सुधार किया।

कानपुर की श्रद्धा दीक्षित बनी एक दिन की डीएम

» सुनी जनसमस्याएं, निस्तारण के लिए अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। जनपद में हाईस्कूल की परीक्षा में टॉपर रही कुमारी श्रद्धा दीक्षित को उनकी इस उपलब्धि के सम्मान में सांकेतिक जिलाधिकारी के रूप में जिला प्रशासन, कानपुर नगर द्वारा दायित्व सौंपा गया। छात्रा ने अपने काम को बखूबी अंजाम दिया और जनसमस्याओं को पहले समझा और फिर संबंधित अफसरों को उनके निस्तारण के लिए सौंपा। इस दौरान जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह छात्रा के पास ही बैठे सारी कार्रवाई को देखते रहे।

बुधवार को मिशन शक्ति 5.0 के अंतर्गत आज जनपद कानपुर नगर में एक विशेष आयोजन किया गया जिसमें पारितोष इंटर कॉलेज, हंसपुरम, नौबस्ता की मेधावी छात्रा कुमारी श्रद्धा

दीक्षित ने एक दिन की जिलाधिकारी के रूप में कार्य किया। छात्रा श्रद्धा दीक्षित ने वर्ष 2025 की हाईस्कूल परीक्षा में 600 में से 581 अंक (96.83%) प्राप्त कर जनपद में टॉपर का स्थान प्राप्त किया था। एक दिन की जिलाधिकारी के रूप में श्रद्धा दीक्षित ने जनता की शिकायतें सुनीं तथा उनके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए।

इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके उत्साह एवं संवेदनशीलता की सराहना की। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति 5.0 का उद्देश्य महिलाओं और बालिकाओं में



आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रशासनिक समझ विकसित करना है। श्रद्धा दीक्षित जैसी प्रतिभाशाली बालिकाएं आने वाले समय में समाज और शासन की दिशा निर्धारित करेंगी। इस आयोजन का उद्देश्य बालिकाओं में नारी सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के

प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा उन्हें सशक्त नेतृत्व का अनुभव प्रदान करना है। जनसुनवाई के दौरान सांकेतिक जिलाधिकारी श्रद्धा दीक्षित के समक्ष मीरपुर छावनी, थाना रेलबाजार निवासी अनीसा पत्नी मोहम्मद सईद द्वारा अपने आवास से संबंधित भूमि

विवाद की शिकायत प्रस्तुत की गई। प्रार्थिनी ने बताया कि कुछ स्थानीय व्यक्तियों द्वारा उनके मकान के सामने अवैध रूप से रास्ता बनाकर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है तथा विरोध करने पर उन्हें डराया-धमकाया जाता है। शिकायत के बावजूद पुलिस द्वारा उचित कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसपर सांकेतिक जिलाधिकारी श्रद्धा दीक्षित ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संबंधित क्षेत्राधिकारी एवं थाना प्रभारी रेलबाजार को आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। इसी प्रकार दर्शनपुरवा समेत कई क्षेत्रों की समस्याओं का निराकरण कराने के लिए सांकेतिक जिलाधिकारी ने आदेश पारित किये।

मोदी-योगी की सरकार राष्ट्रहित व जनकल्याण को समर्पित: राहुल बच्चा

बिल्हौर में जीएसटी उत्सव एवं व्यापारी-उद्यमी सम्मेलन का आयोजन



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर (कानपुर)। बिल्हौर कस्बे के एक गेस्ट हाउस में बुधवार को जीएसटी उत्सव एवं व्यापारी-उद्यमी सम्मेलन का आयोजन भाजपा कानपुर ग्रामीण द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पं. दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण से हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक दिवाकर

मिश्रा ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से न केवल व्यापारियों को बल्कि किसानों और मध्यम वर्ग को भी प्रत्यक्ष राहत मिलेगी। केंद्र और राज्य की डबल इंजन सरकार हर निर्णय में जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। जीएसटी अधिवक्ता पवन गुप्ता ने कहा कि जीएसटी ने एक राष्ट्र-एक कर की अवधारणा को साकार कर दिया है। नई दरों के लागू होने से व्यापार प्रणाली और अधिक पारदर्शी व

» कार्यक्रम में बड़ी संख्या में व्यापारियों व कार्यकर्ताओं ने की सहभागिता।

सरल बनी है। यह सुधार छोटे और मध्यम उद्यमियों के लिए नई ऊर्जा लेकर आया है।

कार्यक्रम संयोजक एवं विधायक राहुल

बच्चा सोनकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार राष्ट्रहित और जनकल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित है। जीएसटी दरों में कमी से व्यापार को नई गति मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

भाजपा मीडिया प्रकोष्ठ के निर्देशानुसार, मीडिया प्रभारी अंशुल बाजपेई ने बताया कि विधानसभा स्तर पर ऐसे सम्मेलन लगातार

आयोजित किए जा रहे हैं, ताकि सरकार की जनहितकारी नीतियों और उपलब्धियों को अधिक प्रभावी ढंग से जनता तक पहुंचाया जा सके। कार्यक्रम में रामशरण कटियार, सुशील कटियार, कौशल अवस्थी, प्रभाकर अवस्थी, जे.पी. कटियार, कुश अग्निहोत्री, ज्वेलर्स व्यापारी उदय शंकर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में व्यापारी, उद्योगपति और भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

महिला से फोन पर बात करने में दो युवक अरेस्ट, भेजे जेल

विवाद और अभद्रता करने की पुलिस को दी थी तहरीर



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर(कानपुर)। ककवन क्षेत्र में महिला से फोन पर बातचीत को लेकर हुआ विवाद दो युवकों को भारी पड़ गया। मामला तूल पकड़ने पर पुलिस ने दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

थानाध्यक्ष जितेन्द्र राजपूत ने बताया कि प्रसादपुरवा निवासी पूजा देवी की शिकायत पर कार्रवाई की गई। उन्होंने अपनी उर्फ दीपक (26) पुत्र बाबूराम और कन्हैया उर्फ

ओमजी (20) पुत्र कमलेश के खिलाफ फोन पर बात को लेकर विवाद और अभद्रता की तहरीर दी थी।

सूचना पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दोनों युवकों को मौके से दबोच लिया। थाने में पूछताछ के बाद दोनों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस का कहना है कि ऐसे मामलों में शांति भंग करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

टोल प्लाजा कर्मियों की मनमानी, परेशान रही महिला परिचालक

निवादा में महिला सशक्तिकरण को टेंगा दिखा रहे निरंकुश कर्मचारी

» काफी मशक्कत के बाद फीस जमा करने पर निकाली बस

» पौन घंटे तक सवारियों को झेलनी पड़ी परेशानी।

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो।

बिल्हौर(कानपुर)। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिला सशक्तिकरण सप्ताह के दौरान शिवराजपुर के निवादा टोल प्लाजा पर रोडवेज की एक महिला परिचालक को फास्टैग स्कैन न होने के कारण 40 मिनट तक परेशान होना पड़ा और उनकी बस को रोके रखा गया। यह घटना प्रदेश सरकार की उन कोशिशों को टेंगा दिखा रही है जो महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए की जा रही हैं।

गौरतलब है कि यदि फास्टैग स्कैन नहीं हो रहा था, तो टोल प्लाजा कर्मियों को वैकल्पिक रूप से कैश लेन में अनुमति देना चाहिए था। जैसा कि बाद में परिवहन निगम के अधिकारियों से वार्ता के बाद किया भी गया। बस में पचास सवारियां होने के कारण तुरंत बस को जाने देना चाहिए था, खासकर



है। यह यात्रियों और परिचालक दोनों के लिए बड़ी परेशानी का कारण बना।

ऐसे उड़ाया जा रहा महिला सशक्तिकरण का मजाक!

महिला सशक्तिकरण सप्ताह जैसे विशेष समय में एक कर्तव्यनिष्ठ महिला कर्मचारी को इस तरह से परेशान करना, सशक्तिकरण के विचार का मजाक उड़ाता है। यह घटना निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) और टोल प्लाजा प्रबंधन दोनों के लिए चिंता का विषय है, और इस पर तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएँ न हों।

सम्पादकीय

दुर्घटना रोकने को तय हो जवाबदेही

यह शर्मनाक ही है कि भारत में दुनिया की सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। इन दुर्घटनाओं में अन्य कारणों के अलावा सबसे अधिक भूमिका तकनीकी व गुणवत्ता की खामियों वाली सड़कों की होती है। यह भयावह है कि वर्ष 2023 में देश में हुई पांच लाख दुर्घटनाओं में करीब पौने दो लाख लोगों की मौत हुई। उस पर सबसे दुखद यह है कि मरने वालों में एक लाख चौदह हजार लोग अद्वारह से 45 वर्ष के बीच के युवा थे। जो परिवार के कमाने वाले व नई उम्मीद थे। इन हालात को देखते हुए ही केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने वर्ष 2030 तक इन सड़क दुर्घटनाओं को आधा करने का लक्ष्य रखा है। यह विडंबना ही है कि दुर्घटनाएं रोकने के लिये सख्त कानून बनाने एवं तकनीक के जरिये चालकों की लापरवाही पर नजर रखने जैसे उपायों के बावजूद आशातीत परिणाम सामने नहीं आए हैं।

ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के बेबाक सुझाव से सहमत हुआ जा सकता है कि खराब सड़क निर्माण को गैर-जमानती अपराध बना दिया जाना चाहिए। इसके लिये ठेकेदार और इंजीनियर की जवाबदेही तय होनी चाहिए। हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के एक कार्यक्रम में उन्होंने दुःख जताया कि विदेशों में होने वाले कार्यक्रमों में जब भारत में विश्व की सर्वाधिक सड़क दुर्घटना वाले देश के रूप में चर्चा होती है, तो उन्हें शर्म महसूस होती है।

आखिर तमाम प्रयासों के बावजूद सड़क हादसे क्यों नहीं थम रहे हैं। यह बात तय है कि अगले पांच सालों में सड़क दुर्घटनाओं को यदि आधा करना

है, तो युद्ध स्तर पर प्रयास करने होंगे। उन कारणों को तलाशना होगा, जिनकी वजह से हर साल सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि होती है। आखिर क्या वजह है कि राजमार्गों के विस्तार और तेज गति के अनुकूल सड़कें बनने के बावजूद हादसे बढ़े हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि राजमार्गों व विभिन्न तीव्र गति वाली सड़कों में साम्य का अभाव है, वहीं मोड़ों को दुर्घटना मुक्त बनाने हेतु तकनीक में बदलाव की जरूरत है। ऐसे में केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को उन कारणों की पड़ताल करनी होगी, जो पर्याप्त धन आवंटन के बावजूद सड़कों को दुर्घटनामुक्त बनाने में बाधक हैं। ऐसे में जरूरी है कि सड़कों की निर्माण सामग्री और डिजाइनों की निगरानी के लिये स्वतंत्र व सशक्त तंत्र बनाया जाए, जो बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के काम कर सके।

साथ ही मंत्रालय का दायित्व बनता है कि इस बाबत स्पष्ट नीति को सख्ती से लागू किया जाए। यह जानते हुए कि सड़कों के ठेके में मोटे मुनाफे के लिए एक समांतर भ्रष्ट तंत्र देश में विकसित हुआ है, जो निर्माण कार्य की गुणवत्ता से समझौता करने से परहेज नहीं करता।

जिसके खिलाफ उठने वाली ईमानदार आवाजें दबा दी जाती हैं। निस्संदेह, गुणवत्ता का मूल्यांकन करने वाली व्यवस्था की जवाबदेही तय करने की सख्त जरूरत है। तब हमें यह सुनने को नहीं मिलेगा कि उद्घाटन के कुछ ही बाद ही सड़क उखड़ गई या बारिश में धुल गई।

शिक्षकों की बाट जोहते सरकारी स्कूल

ज्योति मल्होत्रा

इसी समाचार-पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट के तहत, हरियाणा के सरकारी प्राथमिक व माध्यमिक स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। सर्वाधिक चिंतनीय अवस्था नूंह जिले की है, जहां 901 विद्यालयों में 3,425 शिक्षकों के पद रिक्त पाए गए। विधानसभा के हालिया मानसून सत्र में सरकार ने भी प्रदेश के 14,295 विद्यालयों में 12,000 से अधिक शिक्षक पद रिक्त होने की बात स्वीकारी। समूचे तौर पर सरकारी शैक्षणिक व्यवस्था का संज्ञान लें तो भारत के हर राज्य में कमोबेश यही स्थिति है। दिसंबर, 2023 में, केंद्र सरकार ने प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर क्रमशः 7,22,413 तथा 1,24,262 अध्यापकों की कमी बताई थी। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शिक्षक-पद खाली हैं। गहनतापूर्वक विचारें तो यह अभाव मात्र एक संख्या न होकर समूची शिक्षा व्यवस्था कमजोर करने वाला संकट है। गुणवत्तापूर्वक शिक्षा में सामाजिक, भावनात्मक तथा शारीरिक विकास के साथ-साथ शैक्षणिक उपलब्धि भी शामिल होती है। पर्याप्त शिक्षकों के अभाव में जहां व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करने में कठिनाई आती है, वहीं छात्र समग्र विकास के अवसरों जैसे पाठ्येतर गतिविधियों, मार्गदर्शन आदि से वंचित रह जाते हैं।



(एनसीपीसीआर) की एक रिपोर्ट अनुसार, कई राज्यों में शिक्षक 50-60 या उससे ज्यादा छात्रों की कक्षाओं का प्रबंधन करते हैं। हरियाणा के नूंह, पलवल तथा यमुनानगर जैसे जिलों में 80-100 छात्र पढ़ाने के लिए एक ही शिक्षक नियुक्त है, जबकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के मुताबिक, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर शिक्षक-छात्र अनुपात क्रमानुसार 1:30 तथा 1:35 होना चाहिए। अतिरिक्त कार्यभार जहां शिक्षकों की थकान बढ़ाता है, वहीं मनोबल गिराता है। स्थिति के परिणामस्वरूप रटत विद्या पर निर्भरता बढ़ने के कारण छात्रों की रचनात्मकता तथा आलोचनात्मक सोच ख़ासी प्रभावित होती है। दीर्घकालिक असर के रूप में सामाजिक प्रगति बाधित होती है। दरअसल, शिक्षकों की कमी का जीडीपी प्रतिशत के रूप में शिक्षा के निवेश से गहरा संबंध है। भारत में शिक्षा पर होने वाला सरकारी व्यय जीडीपी के 3-4 प्रतिशत के आस-पास है, जोकि एनईपी 2020 की 6 प्रतिशत आवंटन की सिफारिश तथा वैश्विक औसत से कहीं कम है। कम निवेश सरकार द्वारा योग्य शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा उन्हें बनाए रखने की क्षमता सीमित करता है। शिक्षकों की कमी का गंभीर मुद्दा बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाकर ही निपटाया जा सकता है। समस्या की प्रकृति समझते हुए सरकार मजबूत एवं प्रभावी भर्ती रणनीतियां लागू करे, जिसमें महत्वाकांक्षी शिक्षकों के लिए छात्रवृत्ति, प्रोत्साहन, शैक्षणिक कौशल तथा विषय ज्ञान पर बल देने वाले व्यापक कार्यक्रम भी बराबर शामिल हों। योग्य शिक्षकों की कमी दूर करने हेतु सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों तथा स्थानीय समुदायों के समन्वित प्रयासों की भी महती आवश्यकता है। शिक्षकों की भर्ती, प्रशिक्षण तथा सहायता में अपेक्षित निवेश करके भारत एक अधिक प्रभावी तथा समावेशी शिक्षा प्रणाली बना सकता है, जो सभी छात्रों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करे। इसके साथ ही स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार तथा आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता पर भी ध्यान देना होगा।

स्पष्ट शब्दों में, शिक्षकों की कमी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में एक बड़ी बाधा है, जिसके सीखने के परिणामों, समानता तथा समग्र छात्र विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर एजुकेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार, पर्याप्त शिक्षक सहयोग के बिना छात्रों से अन्य गतिविधियों में भाग लेने की अपेक्षा घटती है, वास्तव में जो उनके सर्वांगीण विकास में काफी हद तक सहायक बन सकती थीं। शिक्षा की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली यह कमी छात्रों की संख्या में गिरावट आने का सबब भी बनती देखी गई। अनेक बार शिक्षकों की कमी के चलते शैक्षणिक सत्र समय पर पूरे नहीं हो पाते। हाशिये पर रहने वाले समुदायों, खासकर ग्रामीण तथा आर्थिक रूप से वंचित इलाकों पर इसका असमान रूप से विशेष असर देखने में आया। इन क्षेत्रों के छात्रों की योग्य शिक्षकों तक पहुंच सीमित होने के कारण शैक्षणिक असमानताएं अपेक्षाकृत बढ़ जाती हैं। यूनेस्को के अनुसार, भारत में पाठशाला न जाने वाले 1.9 करोड़ बच्चों में से बहुतेरे इन्हीं वंचित समुदायों में आते हैं। दूसरे शब्दों में, शैक्षणिक असमानताएं उपजाने के साथ यह कमी शिक्षा तंत्र पर वित्तीय दबाव भी बढ़ा देती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

सरकारी धन से चुनावी रेवड़ियां बांटने के खतरे

चुनाव परिणाम

ज्वाला सिंह दास

राजनीतिक रिश्ततखोरी यानी मतदाता को रेवड़िया बांटकर उन्हें अपने पक्ष में वोट देने के लिए लुभाना। कहा यह भी जा रहा है कि चलो अब कुछ दिन रेवड़ियां बांटने की घोषणाओं से तो पीछा छूटेगा। यहां रेवड़ियों का मतलब वह 'मुफ्त की सेवाएं' हैं जिनका लालच देकर राजनेता मतदाता को बरगलाते हैं। पहले बिजली-पानी जैसी जीवनोपयोगी चीजें मतदाता को दी जाती थीं, देने का वादा किया जाता था, और अब तो यह नकद पैसा बांटा जा रहा है।

बिहार सरकार ने कुछ ही दिन पहले एक करोड़ से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में दस हजार रुपये जमा करवा कर इस रेवड़ी संस्कृति को एक नया आयाम दे दिया है। एक करोड़ महिलाओं का मतलब एक करोड़

परिवारों तक पहुंचना है। महिलाओं के सशक्तीकरण के नाम पर यह सीधी रिश्तत है। सवाल यह पूछा जा रहा है कि किसी सरकार द्वारा इस तरह की नकद राशि बांटना क्या सरकार के पैसों से चुनाव जीतना नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर इसे अपराध की श्रेणी में क्यों न रखा जाये, और यदि यह अपराध है तो फिर इसकी कोई सजा तय क्यों नहीं होनी चाहिए? पूछा तो यह भी गया है कि सरकार द्वारा मुफ्त राशन बांटना भी क्या एक तरह से रेवड़ी बांटना नहीं है? आश्वासन वाली राजनीति कोई नयी चीज नहीं है। और ऊपरी तौर पर देखें तो यह उतनी ग़लत भी नहीं लगती। आखिर जनता के हित की बात सोचना सरकार का काम है, और जनता को वित्तीय सहायता देकर जनता की सहायता ही तो की जाती है। पर सवाल उठता है कि जनता की यह 'मदद' सरकारों और राजनीतिक दलों को



चुनावों से पहले ही याद क्यों आती है? सवाल यह भी उठाना चाहिए कि राजनीति में 'तोहफे' बांटने की यह परंपरा अपराध की श्रेणी में क्यों नहीं आनी चाहिए? चुनाव से कुछ अरसा पहले, या वैसे भी, हमारी सरकारें जनता की मदद की घोषणाएं शुरू कर देती हैं और मीडिया में इसे मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के तोहफे के रूप में प्रचारित किया जाता है। कुछ ही साल पहले चुनाव-प्रचार के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री ने बिहार में खुले आम तोहफों की बोली लगायी थी। एक चुनाव-सभा में उन्होंने कुछ ऐसा कहा था, 'कितने दू, दस करोड़?, सौ करोड़?, हजार करोड़?

या लाख करोड़?' उनकी घोषणा पर श्रोताओं ने तालियां बजाकर इसका स्वागत किया था, निश्चित रूप से इस तोहफे का कुछ असर चुनाव परिणाम पर भी पड़ा होगा। पर चुनावी लाभ के लिए जनता के पैसों के तोहफे इस तरह बांटने की घोषणा क्या विद्रूप पहल नहीं मानी जानी चाहिए? सच तो यह है कि इसे तोहफा या उपहार कहना ही ग़लत है। कहा जा सकता है कि इस तरह की घोषणाएं वर्तमान या भावी सरकार की रीति-नीति बताती हैं, पर बताने की यह आवश्यकता चुनावों के समय पर ही किसी को याद क्यों आती है? ऐसा नहीं है कि इस तरह के सवाल पहले कभी उठे नहीं हैं। उठते रहे हैं ये सवाल, पर राजनीतिक नफा-नुकसान का गणित इन सवालों को उठाने वाली नैतिकता पर अक्सर हावी हो जाता है। कभी महिला मतदाताओं को साड़ियां बांटकर तमिलनाडु की जयललिता ने वोट के

लिए रिश्तत की इस परंपरा की शुरुआत की थी। द्रमुक के ही करुणानिधि ने दो रुपये किलो चावल बांटकर इस शुरुआत को चुनाव जीतने की एक कला के रूप में विकसित किया। फिर तो जैसे देश के अलग-अलग हिस्सों में इस कला को निखारने की एक प्रतिस्पर्धा ही चल पड़ी। ऐसा भी नहीं है कि इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की जरूरत की ओर किसी का ध्यान न गया हो। स्वयं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने इस 'रेवड़ी संस्कृति' को मुद्दा बनाया था। पर जल्दी ही उन्हें यह अहसास हो गया कि यह संस्कृति तो स्वयं उनके लिए भी लाभदायक है और वे भी लाभ लुटाकर लाभ कमाने की इस प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गये। अब तो हमारे राजनीतिक दल यह सोचना भी नहीं चाहते कि इस प्रतियोगिता में राज्यों का बजट घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है।

सियासी जड़ों के लिए पोषण मांगता दरख्त

» आजम खान और अखिलेश यादव की बंद कमरों में मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे

निर्मल तिवारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

रामपुर/लखनऊ। आखिरकार बुधवार यानि आठ अक्टूबर को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और वरिष्ठ नेता सपा के संस्थापक सदस्य आजम खान की मुलाकात संपन्न हो गई। इसी के साथ 23 सितंबर से मीडिया में चल रही अटकलों, सुर्रबाजियों का प्रवाह फिलहाल बाधित हो गया। इस

अटकलबाजी, सियासी संशय, आजम खान के अगले राजनीतिक कदम और सियासी भविष्य पर इतनी हाइप मात्र मीडिया की देन नहीं थी बल्कि इसके लिए संपूर्ण मसाला तो राजनीति के धुरंधर, चतुर सुजान, वाकपटुता के माहिर आजम खान साहब अपनी बातों में दैनता का पुट डालकर और रहस्यमयी बातें कर स्वयं मुहैया करा रहे थे। मुलाकात के बाद जहां अखिलेश यादव ने पत्रकारों के समक्ष अपने हृदय के उद्गार व्यक्त कर आल इज वेल का संदेश दिया तो उनसे एक कदम आगे बढ़कर आजम साहब ने पत्रकारों से ही पूछ लिया कि हमारी नाराजगी वाली सूचना आपको मिली कहां से.....

पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है
मुलाकात के बाद अखिलेश यादव ने उन्हें ऐसा दरख्त कहा जिसका साया हमेशा समाजवादियों पर रहता है। मुलाकात से पहले पत्रकारों से वार्तालाप में एक नहीं अनेक बार आजम खान ने अपने हालात बयान



करते हुए कहा पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। मीर तकरी मीर साहब ने अपनी इस मशहूर गजल में आगे कहा है जाने ना जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है। यह तो निश्चित है कि आजम खान साहब के मन में कुछ अंतर्द्वंद तो था। कुछ ना कुछ कसक कुछ ना कुछ टीस या कहें कोई ना कोई प्रश्न उनके अंतर्मन को उद्देलित तो अवश्य किए हुए था, तभी उन्होंने पत्रकारों के समक्ष उसे बयान किया। अब आजम खान साहब को यह शिकवा शिकायत किससे था या है, हो सकता है इसे समझने में पत्रकार बिरादरी चूक कर गई हो। यह भी हो सकता है राजनीति के धुरंधर आजम खान ने अपना यह तीर निशाने पर लगने के बाद वापस खींच लिया हो। या फिर दूसरी ओर फिर निशाना साध लिया हो क्योंकि

बागवान ने तो दो घंटे की गुप्तगू में अब हाल जान ही लिया है और दरख्त के साए और बुजुर्ग के आशीर्वाद की कामना कर ही दी है।

बूढ़े बरगद को चाहिए सियासी संबल
मुलाकात के बाद अखिलेश यादव के बयान में दरख्त का जिक्र हुआ। निःसंदेह आजम खान एक वटवृक्ष हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी उपयोगिता समाजवादी पार्टी में सिद्ध करते रहे हैं। लेकिन वर्ष 1977 से शुरू हुआ यह सियासी सफर, आजम खान की वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत देखें तो शायद अब एक अधेरी सुरंग की ओर जाता नजर आ रहा है। रूपकों के आधार पर यदि बात आगे बढ़े तो बात निकलती है कि बूढ़े हो रहे इस बरगद ने सुनामी और तूफान का एक साथ सामना किया है और फलस्वरूप बरगद को ऐसा लगता है कि शायद

वर्ष 2016 में अपने एक चर्चित बयान में आजम साहब ने कहा था उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की सारी अच्छाइयां होते हुए भी वह प्रधानमंत्री नहीं बन सकते क्योंकि एक कमी है कि वो मुसलमान हैं। इससे उनके सियासी विचारों की बाजगी मिलती है। ऐसी बाजगी तो उनके राजनीतिक सफर के हर मोड़ पर उपलब्ध है। फिर चाहे कारगिल विजय को लेकर 2013 में दिया गया उनका बयान हो या मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर उनके विचार, उन्होंने हमेशा मुस्लिम समाज की पैरोकारी की। लेकिन वही आजम साहब बदली राजनीतिक फिजाओं में अब इंसानियत की बात कर रहे हैं। इस तथ्य से एक बात सामने आती है कि आजम खान साहब ने जिस आधार के सहारे अपनी सियासी इमारत खड़ी की थी, वह आधार, वो तैवर आज की राजनीति में प्रासंगिक नहीं रहे। इसका अर्थ है कि आजम साहब की राजनीतिक इमारत आज आधार विहीन हो चुकी है। इस आधारहीन इमारत को आधार केवल और केवल अखिलेश यादव ही दे सकते हैं। अखिलेश यादव अपने इस बुजुर्ग नेता, सपा के संस्थापक सदस्य आजम खान साहब की सियासी इमारत की नींव कैसे मजबूत करेंगे यह तो भविष्य के गर्भ में और अखिलेश यादव के मन में है। क्योंकि मुलाकात के संबंध में अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा है

वया कहें उस मुलाकात की दास्तान जहां जग्गताओं ने खामोशी से बात की।

जड़ें कमजोर हो गई हैं। ऐसी स्थिति में बरगद को अब सहारा चाहिए। कानूनी लड़ाई जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही महत्वपूर्ण या कहें उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है सियासी उपयोगिता और उपस्थिति बनी रहे। साथ ही सियासी जमीन खिसकने ना पाए तभी बरगद की जड़े मजबूती पाएंगी।

प्रासंगिकता पर प्रश्नचिन्ह

आजम खान हों या फिर उनकी पत्नी या बेटा अब्दुल्ला, आज की तारीख में चुनाव लड़ने के अयोग्य हैं। तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि सियासी फिजाओं में उपस्थिति दर्ज होगी तो कैसे? शायद पिछले एक पखवाड़े में आजम साहब के बयानों से जो सबसे बड़ी चिंता उभर कर आती है वह यही हो सकती है कि वर्तमान कालखंड और इन विषम परिस्थितियों में आजम खान सपा के लिए कितने प्रासंगिक हैं। आखिर यह किसी से छुपा नहीं है कि वर्तमान समय में रामपुर से जो

सपा के सांसद हैं उन्हें आजम खान की मर्जी के खिलाफ जाकर टिकट दिया गया। आजम सब अपनी इस नापसंदगी को छुपाते भी नहीं हैं। सपा ने अपने गठन के बाद आम चुनाव में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन 2024 के चुनाव में किया और उसमें प्रत्यक्षत-आजम साहब का कोई योगदान भी नहीं है। वर्तमान समय में आजम साहब यह दावा भी नहीं कर सकते कि मुसलमानों ने उनका चेहरा देखकर सपा को वोट दिया। आज का कटु सत्य यह है कि मुस्लिम समाज के पास सपा का दूसरा कोई विकल्प हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में है ही नहीं। यहीं से आजम साहब के अंतर मन में यह प्रश्न गंभीरता से उठना लाजिमी है कि वर्तमान सपा में उनकी प्रासंगिकता क्या है? इसे यदि और संवर्धित किया जाए तो प्रश्न यह भी उठता है कि वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में आजम खान साहब प्रासंगिक हैं या नहीं!

खेलते समय लापता हुई बच्ची, सुबह कुएं में उतराता मिला शव

» परिजनों में मचा कोहराम, जांच शुरू



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। घाटमपुर के शाखा जनवारा गांव में बुधवार शाम खेलते समय लापता हुई सात वर्षीय बच्ची का शव गुरुवार सुबह कुएं में उतराता मिला। रात भर पुलिस और परिजन तलाश करते रहे थे, अब शव को

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। कानपुर में रेउना थाना क्षेत्र के शाखा जनवारा गांव में बुधवार की शाम खेलते समय लापता हुए एक सात वर्षीय बच्ची का शव गुरुवार सुबह कुएं में उतराता मिला। बच्ची बुधवार शाम को खेलते समय अचानक लापता हो गई थी। रात भर परिजन और पुलिस मिलकर बच्ची को खोजते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। गुरुवार सुबह बच्ची का शव गांव के पास एक कुएं में उतराता हुआ पाया गया। कुएं की बाउंड्री होने के चलते आशंका जताई जा रही है कि बच्ची खेलते समय उसमें गिर गई होगी।

विश्व बैंक एच ब्लॉक में मिनी ट्यूबवेल स्थापना को हरी झंडी

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। वार्ड नंबर 45 विश्व बैंक बर्बा के अंतर्गत एच ब्लॉक के लिए पेयजल संकट से राहत की बड़ी सौगात मिली है। नगर निगम सदन में पार्षद रेनु अर्पित यादव द्वारा प्रस्तुत मिनी ट्यूबवेल स्थापना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।

महापौर प्रमिला पांडेय द्वारा पार्षदों को प्रथम किशत में 20 लाख रुपये और दूसरी किशत में 12 लाख रुपये की निधि आवंटित की गई थी। इसी निधि से पार्षद रेनु अर्पित यादव ने लगभग 25 लाख रुपये की लागत से एच ब्लॉक में मिनी ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया, जिसे 8 अक्टूबर 2025 को हुई सदन की बैठक में स्वीकृति प्रदान की

» 15 हजार आबादी को मिलेगा पेयजल संकट से राहत



पार्षद अर्पित यादव

गई इस परियोजना से करीब 15 हजार की आबादी को राहत मिलेगी। क्षेत्र में लंबे समय से लो प्रेशर और जल संकट की समस्या बनी हुई थी, जिससे लोगों को

दैनिक जीवन में भारी असुविधा झेलनी पड़ती थी। मिनी ट्यूबवेल लगने से अब एच ब्लॉक की जनता को नियमित पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित होगी। स्थानीय नागरिकों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए हर्ष व्यक्त किया। इस अवसर पर राम कुमार सिंह, गणेश शंकर त्रिपाठी, किरण साहू, उषा कटियार, अतुल द्विवेदी, मोहन वर्मा, प्रियम मिश्रा, गौरव श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंद्र, गुड्डन दुबे सहित क्षेत्र के अनेक लोग उपस्थित रहे। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह पहल क्षेत्र के विकास की दिशा में एक अहम कदम है, जिससे आने वाले समय में जल संकट से पूरी तरह निजात मिल सकेगी।

जिला अस्पताल में अनाधिकृत दवा लिखने के मामले पर जांच समिति गठित

स्वराज इंडिया की खबर का असर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। स्वराज इंडिया की खबर का बड़ा असर अब जिला अस्पताल में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कमरा नंबर तीन में अनाधिकृत व्यक्ति द्वारा बाहरी दवाएं लिखने के गंभीर खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। मामले का संज्ञान लेते हुए प्रभारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) डॉ. राजेश सिंह ने तत्काल कार्रवाई करते हुए तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन कर दिया है।

इस समिति में सर्जन डॉ. ए.के. सिन्हा, नेत्र सर्जन डॉ. विजय हरि

आर्या और चीफ फार्मासिस्ट प्रभा शंकर द्विवेदी को शामिल किया गया है। कमेटी को तीन दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि स्वराज इंडिया ने इस घोटाले का खुलासा करते हुए बताया था कि जिला अस्पताल के कमरा नंबर तीन में संदीप यादव नामक एक अनाधिकृत व्यक्ति मरीजों को बाहरी दवाएं लिख रहा था।

इस दौरान उसकी तस्वीर भी वायरल हुई थी, जिससे स्वास्थ्य

विभाग में हड़कंप मच गया। जांच समिति के सदस्य ने बताया कि वे मामले की गहराई से जांच करेंगे और यह भी देखेंगे कि क्या यह किसी बड़े रैकेट का हिस्सा है।

प्रभारी सीएमएस डॉ. राजेश सिंह ने कहा, मरीजों का स्वास्थ्य और अस्पताल की साख सर्वोपरि है। दोषी पाए जाने वालों पर कठोर कार्रवाई तय है। जनता अब इस जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रही है, जिसने जिला अस्पताल की कार्यप्रणाली पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं।



अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के अबूधाबी में बुर्का पहनने पर विवाद, पुजारी राजू दास ने जताया एतराज

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

दीपिका पादुकोण के अबूधाबी में बुर्का पहनने पर विवाद हो गया है। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने इस पर तंज सका है। फिल्म अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के अबूधाबी में बुर्का पहनकर वहां पर पर्यटन का प्रचार करने पर विवाद खड़ा हो गया है। अयोध्या की प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने इस प्रकरण में दीपिका पर निशाना साधा है।

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा था कि दीपिका पादुकोण अबूधाबी में बुर्का पहनकर एक शो का प्रचार कर रही हैं। यही दीपिका जब भारत में रहती है तो जेएनयू में माई फ्रीडम का नारा लगाती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दीपिका की भारत में मानसिकता दूसरी हो जाती है और इस्लामिक देश में कुछ और हो जाती है। भारत में कम कपड़ों में घूमती हैं और विदेश में बुर्का पहन लेती हैं। इसके पीछे दीपिका की क्या मजबूरी है। यह मानसिकता दर्शाती है कि भारत में इतनी फ्रीडम है कि जो आपका दिल करे बोल सकते हैं, जो मन करे पहन सकते हैं और खा सकते हैं जबकि इस्लामिक देशों में इस्लाम धर्म के अनुरूप ही चलना होता है। इससे साफ पता चलता है कि फ्रीडम कहां पर है। यह गंभीर विषय है। भारतवासियों को दीपिका पादुकोण जैसे लोगों से सावधान रहना होगा।

जेल में महिला बन्धियों के लिए आत्मनिर्भर कौशल विकास प्रशिक्षण शुरू

» एसपी श्रद्धा पांडेय ने बच्चों को दिए उपहार, बढ़ाया हौसला



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिला कारागार कानपुर देहात में महिला बन्धियों के पुनर्वास और आत्मनिर्भरता की दिशा में गुरुवार को एक नई पहल हुई। पुलिस अधीक्षक श्रद्धा नरेन्द्र पांडेय ने दीक्षालय फाउंडेशन के सहयोग से 'आत्मनिर्भर कौशल विकास केन्द्र' का शुभारंभ किया। इस केन्द्र के तहत महिला बन्धियों को सिलाई प्रशिक्षण देकर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।

बच्चों को मिला दुलार, बढ़ा आत्मविश्वास

कार्यक्रम के दौरान एसपी श्रद्धा पांडेय ने महिला बन्धियों से संवाद किया और उनके साथ रह रहे पाँच बच्चों को खिलौने और उपहार दिए। यह दृश्य कारागार परिसर में भावनात्मक माहौल लेकर

(सशक्तिकरण की नई पहल)

आया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में बन्धियों के लिए ब्यूटी पार्लर और मोमबती निर्माण जैसे प्रशिक्षण भी शुरू किए जाएंगे,

ताकि उन्हें अधिक रोजगारपरक अवसर मिल सकें। यह पहल केवल प्रशिक्षण तक सीमित नहीं, बल्कि महिला बन्धियों के आत्मविश्वास और

स्वाभिमान को पुनर्जीवित करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। कानपुर देहात पुलिस और दीक्षालय फाउंडेशन की यह साझेदारी समाज में सुधार और पुनर्वास की नयी मिसाल बन सकती है।

जेल में 57 महिला बन्दी

वर्तमान में जेल में 57 महिला बन्दी निरुद्ध हैं, जिनमें 43 विचाराधीन और 14 सजायापता हैं। इनमें से पांच महिलाएं अपने छोटे बच्चों के साथ रह रही हैं।

एसपी ने उनके जीवन स्तर और सुविधाओं का जायजा लेते हुए जेल प्रशासन को आवश्यक सुधारों के निर्देश दिए।

ठंड में मांसपेशियों को सक्रिय और गर्म बनाए रखना जरूरी

» आयुष और फिजियोथेरेपी के संयुक्त उपचार पर जोर देते हुए दी गई उपयोगी जानकारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। चिकित्सा अधीक्षक डॉ. बृजेश आर्य के मार्गदर्शन में 50 शैय्या एकीकृत आयुष चिकित्सालय में शीत ऋतु के आगमन पर एक विशेष चिकित्सा गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का उद्देश्य ठंड के मौसम में बढ़ने वाली स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम, उपचार और जागरूकता पर जनहित में चर्चा करना था। कार्यक्रम में आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी और फिजियोथेरेपी विशेषज्ञों ने शीत ऋतु में अपनाई जाने वाली उपयोगी चिकित्सा विधियों पर अपने विचार साझा किए।

डॉ. बृजेश आर्य ने कहा कि ठंड के मौसम में शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने से रोगों का खतरा बढ़ जाता है। आयुष चिकित्सा पद्धतियाँ शरीर के दोषों (वात, पित्त, कफ) को संतुलित रखती हैं, जबकि फिजियोथेरेपी शरीर

आयुष चिकित्सालय में शीत ऋतु स्वास्थ्य गोष्ठी का हुआ आयोजन



की गतिशीलता, लचीलापन और मांसपेशीय कार्यक्षमता को बनाए रखने में सहायक होती है। उन्होंने बताया कि पंचकर्म चिकित्सा के माध्यम से शरीर से विषैले तत्वों का निष्कासन कर सर्दियों में होने वाले जोड़ों और मांसपेशियों के दर्द से राहत पाई जा

सकती है। डॉ. उत्तम कुमार ने कहा कि शीत ऋतु में वात दोष की वृद्धि से जोड़ों में दर्द, अकड़न और नसाँ में खिंचाव की समस्या आम होती है। ऐसे में स्नेहन (मसाज), स्वेदन (स्टीम थेरेपी) और अभ्यंग (तेल मालिश) अत्यंत

लाभकारी हैं। डॉ. जीशान अंसारी ने यूनानी चिकित्सा के दृष्टिकोण से बताया कि सर्दियों में शरीर का बलगमी मिजाज बढ़ जाता है, जिससे आर्थराइटिस, सर्दी-जुकाम, खांसी और सांस की तकलीफें बढ़ जाती हैं। उन्होंने सुफूफ़-ए-मुसकिन, हब्बे असगंध, रौगन-ए-मस्ख जैसी यूनानी औषधियों और अदरक, लहसुन, खजूर व दूध में शहद जैसे गर्म तासीर वाले खाद्य पदार्थों को उपयोगी बताया।

डॉ. कमलेश प्रजापति ने बताया कि होम्योपैथिक चिकित्सा में भी सर्दियों की बीमारियों का प्रभावी समाधान है।

फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ डॉ. मो. जियाउर्रहमान ने कहा कि ठंड में मांसपेशियों को सक्रिय और गर्म बनाए रखना बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि मैन्जुअल थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी,

पी.एन.एफ., एन.डी.टी. और फंक्शनल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन (स्रथ्स) जैसी तकनीकें मांसपेशियों के लचीलापन, संतुलन और शक्ति को बढ़ाती हैं। साथ ही उन्होंने संतुलित आहार, विटामिन डी, कैल्शियम और पर्याप्त धूप को स्वास्थ्य संरक्षण में आवश्यक बताया।

कार्यक्रम के अंत में सभी विशेषज्ञों ने यह मत व्यक्त किया कि सर्दियों में आयुष और फिजियोथेरेपी के संयुक्त उपचार से न केवल रोगों की रोकथाम बल्कि पुनर्वास भी प्रभावी रूप से किया जा सकता है।

गोष्ठी में पंचकर्म विभाग से योगेंद्र बाबू, सचिन मिश्रा, अमित पटेल, अनुपम पांडे, ज्योति त्रिपाठी, अजय सिंह, विनय सिंह, फार्मासिस्ट रामकुमार, विनोद और योगेश मिश्रा उपस्थित रहे।

अखाड़े में दिखाए कुश्ती के दांव-पेंच, संजू पहलवान बने 'दंगल केसरी'

» रोमांचक मुकाबलों में पहलवानों ने दिखाया अपना दम, दर्शकों में जबरदस्त उत्साह

» सौ साल पुरानी परंपरा में यूपी, हरियाणा और दिल्ली के नामी पहलवानों ने की शिरकत

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। शरद पूर्णिमा के पावन अवसर पर कानपुर देहात के मंगटा गांव में आयोजित ऐतिहासिक पारंपरिक दंगल महोत्सव में अखाड़ों के सितारों ने दमखम और जोश से भरपूर प्रदर्शन किया। सौ वर्ष से अधिक पुरानी इस ग्रामीण परंपरा में इस बार भी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के नामी पहलवानों ने भाग लिया। गांव के बाहर स्थित पुनीत पांडे के खेत में आयोजित दंगल का शुभारंभ पूर्व ग्राम प्रधान सुरेश सिंह ने सलमान (घाटमपुर) और अभिषेक (हरदोई) की पहली कुश्ती के हाथ मिलवाकर किया।

लगभग आधे घंटे तक चली इस जोरदार भिड़ंत के बाद मुकाबले को बराबरी पर समाप्त घोषित किया गया। इसके बाद एक से बढ़कर



एक रोमांचक मुकाबले होते रहे। महेंद्र (कानपुर) ने अपने जबरदस्त दांवों से अनिल (कानपुर नगर) को पछाड़ा, जबकि सबसे चर्चित मुकाबला संजू (कानपुर नगर) और बल्ली (फिरोजाबाद) के बीच हुआ। कुछ ही मिनटों में संजू ने बल्ली को चित्त कर अखाड़े में अपनी बादशाहत साबित कर दी।

उनके शानदार प्रदर्शन पर निर्णायक मंडल ने उन्हें 'दंगल केसरी' के खिताब से नवाजा। कार्यक्रम में ग्रामीणों और दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ी। भारत माता की जय और जय

बजरंगबली के नारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। मंच पर राजेंद्र मिश्रा, सुरेश सिंह चौहान (पूर्व प्रधान), जीत बहादुर सिंह, केशव सिंह चौहान, रामराज सिंह, मोनू सिंह, अतुल सिंह, रवि सिंह, धनंजय सिंह सहित बड़ी संख्या में कुश्ती प्रेमी मौजूद रहे।

शरद पूर्णिमा पर हर साल आयोजित होने वाला मंगटा गांव का यह ऐतिहासिक दंगल न सिर्फ ग्रामीण परंपरा की पहचान है, बल्कि यह युवाओं में खेल भावना और शारीरिक सौष्ठव के प्रति जागरूकता का भी प्रतीक बन चुका है।

रूरा, अकबरपुर की परिवहन व्यवस्था बिगड़ी, चार रोडवेज बसें ही सहारा

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। अकबरपुर में डेढ़ करोड़ की लागत से बन कर तैयार हुए सिटी बस स्टैंड से परिवहन व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद जगी थी, एक सितंबर से कानपुर होकर लखनऊ जाने के लिए चार रोडवेज की बसें भी संचालित कर दी गईं, लेकिन इसके बाद भी परिवहन व्यवस्था बेपटरी है। इसके पीछे के कारण है कि सालों से चल रही 28 सीएनजी बसें मियाद पूरी करने के कारण बंद कर दी गई हैं। अब रूरा, अकबरपुर वासियों के लिए रोडवेज की चार बसें ही सहारा हैं। सिटी बस चलने से रूरा के लोग आसानी से अकबरपुर व जिला मुख्यालय पहुंच जाते थे। वहीं, अकबरपुर से कानपुर जाने के लिए लोगों को काफी सहूलियत थी। अकबरपुर से हर आधे घंटे में बस मिलने पर दैनिक यात्रियों के अलावा, छात्र, व्यापार के सिलसिले से आने वाले व्यापारी सुरक्षित सफर करते थे। सबसे ज्यादा सुविधा सुबह नौकरी करने के लिए कलवट्रेट, कचहरी, मेडिकल कॉलेज व अन्य सरकारी दफतरो में आने वाले लोगों को थी। इन्हीं बस से लोग वापस भी चले जाते थे। इस तरह सुबह से लेकर शाम तक 500 से अधिक लोग सफर करते थे।

सितंबर माह की शुरुआत से अक्टूबर के पहले सप्ताह तक धीरे-धीरे कर सभी 28 सिटी बंद कर दी गई हैं। अब रूरा से अकबरपुर आने व अकबरपुर से कानपुर जाने के लिए कोई सीधा व सुरक्षित साधन नहीं है। ऑटो व अन्य डग्गामार वाहन अधिक किराया वसूल रहे हैं। इतना ही नहीं क्षमता से अधिक सवारी बैठाकर चलने पर सफर भी खतरों भरा है। दैनिक यात्रियों के साथ व्यापारी वर्ग काफी परेशान है। इसको लेकर बसें चलाए जाने की मांग उठने लगी है। वहीं जिम्मेदार भी अभी तक परिवहन व्यवस्था पहले से बेहतर करने के लिए कोई ठोस रणनीति नहीं बना सके। अकबरपुर बस अड्डा भले ही पूरी तरह से गुलजार नहीं हो सका है। मगर परिवहन निगम ने चार बसें कानपुर होते हुए लखनऊ के लिए चला रहा है। यह बसें अकबरपुर बस स्टैंड के पास रुकने के बाद सवारियां लेकर जाती हैं। मगर बस अड्डे पर नहीं खड़ी होती। इनमें से पहली बस अपराह्न 11:00 बजे, दूसरी बस दोपहर 12 बजे, तीसरी बस दोपहर एक बजे, चौथी बस दोपहर दो बजे हैं। मगर शाम के समय के पांच बजे के बाद से ही सत्राटा छा जाता है।

हाईवे से लेकर स्कूल बस तक, सड़क सुरक्षा पर अब डीएम खुद रखेंगे नजर

» बिना नम्बर प्लेट और ओवरलोड वाहनों पर चलाया जाएगा अभियान

» स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच और चालकों के चरित्र सत्यापन के आदेश

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। जिलाधिकारी कपिल सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की अहम बैठक बुधवार को मां मुक्तेश्वरी देवी समागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम, ट्रैफिक प्रबंधन, ब्लैक स्पॉट सुधार, सुरक्षा संकेतक और जन-जागरूकता कार्यक्रमों की विस्तार से समीक्षा की गई। डीएम कपिल सिंह ने अफसरों को सख्त लहजे में निर्देश दिए कि हाईवे किनारे अवैध अतिक्रमणों को तत्काल हटाया जाए ताकि दुर्घटनाओं की संभावना कम हो सके। उन्होंने ज़ांसी हाईवे पर पैचवर्क को दोबारा दुरुस्त कराने, स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और सुरक्षा

मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा।

डीएम ने परिवहन विभाग को निर्देशित किया कि बिना नम्बर प्लेट, ओवरलोड और गलत दिशा में चलने वाले वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही, हेलमेट और सीट बेल्ट पहनना पूर्णतः अनिवार्य किया जाए, उल्लंघन पर प्रभावी चालान कार्रवाई सुनिश्चित हो। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जनपद के सभी स्कूली वाहनों की फिटनेस जांच अनिवार्य रूप से कराई जाए। जो वाहन मानकों पर खरे नहीं उतरते, उन्हें



तुरंत संचालन से बाहर किया जाए। सभी चालकों के चरित्र प्रमाण पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन भी अनिवार्य किया जाएगा। गोल्डन आवर के भीतर राहत व बचाव

डीएम ने कहा कि सड़क दुर्घटना की सूचना मिलते ही गोल्डन आवर के भीतर राहत व बचाव कार्य शुरू किया जाए, ताकि जान-माल की हानि को

न्यूनतम किया जा सके। साथ ही, सड़क सुरक्षा माह के तहत स्कूलों, कॉलेजों और ग्राम पंचायतों में शपथ, रैली, पोस्टर प्रतियोगिता, नुक्कड़ नाटक और प्रचार वाहनों के जरिए जन-जागरूकता अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए लोक

निर्माण, पुलिस, परिवहन, स्वास्थ्य, शिक्षा, नगर निकाय व ऊर्जा विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। बैठक में एडीएम (प्रशासन) अमित कुमार, डीआईओएस, लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता, संभागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

स्वदेशी को राष्ट्रीय अभियान बनाने को रनियां में जुटे व्यापारी

राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला बोलीं, महिला उद्यमी और युवा स्टार्टअप्स 'मेक इन इंडिया' की रीढ़



» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत बुधवार को रनियां में भारतीय जनता पार्टी द्वारा व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य आयोजक प्रदेश सरकार की राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला रही। सम्मेलन में जिले भर से सैकड़ों व्यापारी और उद्यमी शामिल हुए। मंच पर मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व जिलाध्यक्ष कौशल किशोर दीक्षित, भाजपा जिलाध्यक्ष रेणुका सचान और उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष अनुभव अग्रवाल उपस्थित रहे। कौशल किशोर दीक्षित ने अपने संबोधन में कहा कि

यह सम्मेलन केवल आर्थिक विमर्श नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का संकल्प है। उन्होंने कहा हम यहां उस विचार को सशक्त करने के लिए एकत्र हुए हैं जो केवल अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मा से जुड़ा हुआ है।

वहीं जिलाध्यक्ष रेणुका सचान ने कहा कि स्वदेशी अपना आर्थिक नहीं, बल्कि भावनात्मक निर्णय है। हर भारतीय उत्पाद में एक परिवार, एक श्रमिक और एक भारत के सपने की झलक होती है। आत्मनिर्भर भारत की शक्ति महिलाएं और युवा राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने कहा कि मिशन स्वदेशी की असली शक्ति महिलाएं और युवा हैं। प्रदेश में हजारों स्वयं सहायता

समूह और स्टार्टअप्स मेक इन इंडिया की भावना से कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट जेन जीएसटी व्यवस्था छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को पारदर्शी एवं सशक्त व्यापारिक वातावरण दे रही है। राज्यमंत्री ने सभी व्यापारियों से आह्वान किया कि वे स्वदेशी को अपनाएं और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बनें। कार्यक्रम में पूर्व जिलाध्यक्ष राजेंद्र सिंह चौहान, मदन पांडेय, बालजी शुक्ला, रविशशि द्विवेदी, महेश तिवारी, धर्मेन्द्र कुशवाहा, शिवबाबू गुप्ता, सतीश गुप्ता, बीनू मिश्रा, नरेंद्र तिवारी, संजय पांडेय समेत कई प्रमुख भाजपा पदाधिकारी एवं व्यापारी शामिल।

आत्मनिर्भर और सुरक्षित महिला ही सशक्त समाज की नींव

» मिशन शक्ति के तहत रनियां में जागरूकता अभियान चलाया

» महिला हेल्पलाइन नंबर, साइबर सुरक्षा की दी गई जानकारी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति फेज 5.0 अभियान के तहत महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के प्रति जागरूक करने का कार्य निरंतर जारी है। इसी क्रम में गुरुवार को रनियां नगर पंचायत स्थित एस फिटनेस हब जिम सेंटर में विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मिशन शक्ति प्रभारी रीना गौतम ने जिम में प्रशिक्षण ले रही बालिकाओं और छात्राओं को महिला सुरक्षा से जुड़ी अहम जानकारियां दीं। उन्होंने महिला हेल्पलाइन 1090, आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, एंबुलेंस सेवा 108 और महिला हेल्पडेस्क जैसी सरकारी सुविधाओं के

उपयोग के तरीके समझाए। साथ ही उन्होंने साइबर अपराधों से बचाव, ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने और सोशल मीडिया पर सुरक्षा सावधानियों की जानकारी भी साझा की। इस अवसर पर रनियां थाना प्रभारी शिवनारायण सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत थाना स्तर पर लगातार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य महिलाओं, छात्राओं और बालिकाओं को आत्मरक्षा, साइबर सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम में एस फिटनेस हब जिम सेंटर के संचालक सानू यादव और जीतू यादव ने कहा कि ऐसे प्रयास समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा के भाव को मजबूत करते हैं तथा युवाओं को भी जागरूक होने की प्रेरणा देते हैं।



मायावती के आह्वान पर लखनऊ में बसपा का शक्ति प्रदर्शन

» काशीराम स्मारक में उमड़ा जनसैलाब, मायावती ने भरी चुनावी हुंकार

» जिलाध्यक्ष कुलदीप गौतम के नेतृत्व में कानपुर से भी पहुंचे हजारों समर्थक

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

लखनऊ। लंबे समय बाद राजधानी की सड़कों पर फिर से बहुजन समाज पार्टी के नीले झंडे लहराए। सोमवार को बसपा संस्थापक काशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर आयोजित विशाल जनसभा में पार्टी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। राज्यभर से पहुंचे कार्यकर्ताओं ने काशीराम स्मारक स्थल पर जमकर नारे लगाए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय। बसपा सुप्रीमो मायावती के नेतृत्व में पार्टी ने आगामी



विधानसभा चुनावों से पहले अपनी संगठनात्मक ताकत दिखाने की कोशिश की। कार्यक्रम स्थल और रमाबाई मैदान के

आसपास सुबह से ही भीड़ उमड़ पड़ी। हजारों समर्थक ट्रेन और बसों से लखनऊ पहुंचे थे। काशीराम स्मारक परिसर में जगह-जगह नीले

बैनर, झंडे और हाथी के प्रतीक चिह्नों से पूरा वातावरण बसपा रंग में रंगा दिखाई दिया।

मंचों पर दिखी बसपा की 'सोशल इंजीनियरिंग'

कार्यक्रम स्थल पर दो मंच बनाए गए। मुख्य मंच पर खुद मायावती और सोशल इंजीनियरिंग के सात चेहरे मौजूद रहे, जबकि दूसरे मंच पर प्रदेश स्तरीय समन्वयक और पदाधिकारियों को स्थान दिया गया। कानपुर से जिला अध्यक्ष कुलदीप गौतम और युवा नेता रवि गुप्ता के नेतृत्व में हजारों बसपा कार्यकर्ता शामिल हुए। रवि गुप्ता ने कहा कि अब समय है बहुजन समाज को फिर से संगठित करने का ताकि प्रदेश में एक बार फिर बहन मायावती की सरकार बने। सभा के दौरान बसपा नेताओं ने संगठन की मजबूती, दलित-पिछड़ा एकता और मायावती के नेतृत्व में 'सरकार बनाओ, अधिकार पाओ' का नारा बुलंद किया।

सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल में 'कॉमफेस्ट 2025' का भव्य आगाज

» तीन दिवसीय तकनीकी-सांस्कृतिक-साहित्यिक महोत्सव में देश-विदेश के 30 प्रतिष्ठित विद्यालयों की भागीदारी

» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर। सेठ आनंदराम जैपुरिया स्कूल में बुधवार को भारत के सबसे बड़े छात्र-आयोजित वार्षिक तकनीकी-सांस्कृतिक-साहित्यिक महोत्सव 'कॉमफेस्ट 2025' का शुभारंभ हर्षोल्लास के साथ हुआ। यह तीन दिवसीय आयोजन 9 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा।

कॉमफेस्ट का उद्घाटन सनैपचैट के प्रबंध निदेशक और विद्यालय के पूर्व छात्र पुलकित त्रिवेदी ने दीप प्रज्वलित कर किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य गणेश

प्रसाद तिवारी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यालय के नेतृत्व दल के सदस्य और शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत एक ऊर्जावान और प्रतिभाशाली डीजे प्रतीक गोयल (ओमेन) के जोशीले गीतों से हुई, जिनकी प्रस्तुति ने विद्यार्थियों और दर्शकों में उत्साह का संचार किया। इस बार के कॉमफेस्ट में बांग्लादेश के चटगांव ग्रामर स्कूल सहित देशभर के 30 प्रतिष्ठित विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने तकनीकी दक्षता, साहित्यिक प्रतिभा, रचनात्मकता और मानसिक कौशल का शानदार प्रदर्शन किया। पहले दिन 'टेक्नो वार्म-अप' जैसे तकनीकी कार्यक्रमों और मुख्य आकर्षण 'सीएफ एपिसोड' में छात्रों ने दिए गए विषयों पर नाटक प्रस्तुत कर सबका मन मोह लिया। कॉमफेस्ट 2025 का यह संस्करण न केवल विद्यार्थियों की प्रतिभा को मंच देने वाला मंच है, बल्कि यह शिक्षा, तकनीक और संस्कृति के संगम का जीवंत उदाहरण भी बन गया है।



फिल्मी दुनियां में शेमारू जोश पर फेस्टिव मूवी धमाका शुरू

» 21 दिन, 21 ब्लॉकबस्टर!



» स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

मुंबई। इस अक्टूबर महीने में दर्शकों के लिए मनोरंजन का तगड़ा डोज़ लेकर आ रहा है शेमारू जोश। दशहरे से लेकर दिवाली तक चलेगा 21 दिन का ब्लॉकबस्टर फिल्म फेस्टिवल, जिसमें हर दिन दिखाई जाएगी एक सुपरहिट फिल्म। इस अभियान का थीम है - 21 दिन, 21 ब्लॉकबस्टर, यानी त्यौहारों के साथ-साथ सिनेमा का भी धमाकेदार जश्न।

त्यौहारों की चमक और बॉलीवुड के जादू के मेल से यह अक्टूबर दर्शकों के लिए किसी मिनी थिएटर अनुभव से कम नहीं होगा। फेस्टिवल मूड में शेमारू जोश पेश कर रहा है एक्शन, कॉमेडी, रोमांस और ड्रामा का शानदार संगम। फिल्मों की इस खास श्रृंखला में शामिल हैं 'केजीएफ-चैप्टर 1', 'एनिमल', 'तू झूठी मैं मक्कार', 'भूल भुलैया 2' और 'कांतारा' जैसी सुपरहिट फिल्में। रोमांच से लेकर

भावनाओं तक, हर मूड और हर जज्बात के लिए दर्शकों को मिलेगा कुछ नया और यादगार। गांधी जयंती पर शेमारू जोश ने दर्शकों के लिए खास तोहफा तैयार किया है - 'लगे रहो मुन्ना भाई', जिसने 'गांधीगिरी' को नये अंदाज़ में परिभाषित किया था।

वहीं, अक्टूबर में महानायक अमिताभ बच्चन के जन्मदिन को मनाने के लिए 'जश्न-ए-बच्चन' पेशकश के तहत दिखाई जाएगी उनकी कुछ बेहतरीन फिल्में, जो बिग बी के चाहने वालों के लिए खास होंगी। शेमारू जोश ने इस पूरे महीने को एक 'सिनेमा गिफ्ट बॉक्स' की तरह पैक किया है, जिसमें मनोरंजन, यादें और जश्न - सब कुछ मिलेगा एक साथ तो इस त्यौहार, दीप जलाइए, पॉपकॉर्न उठाइए और अपने घर को बनाइए सिनेमा हॉल। दशहरे से दिवाली तक - देखिए 21 दिन, 21 ब्लॉकबस्टर सिर्फ शेमारू जोश पर

राममंदिर के सामने खड़ा अवैध होटल साम्राज्य, अफसर आंख मूंदे पड़े

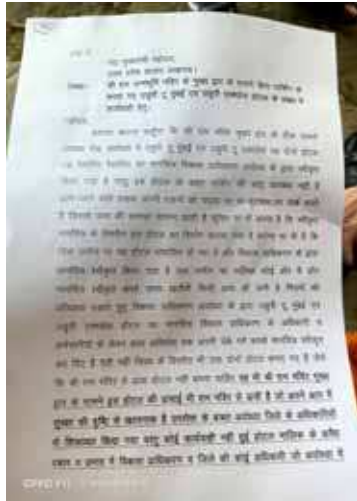
» जब भ्रष्टाचार की ईंटों पर खड़ा हो गया विकास प्राधिकरण का 'विश्वासघात'!

» उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन के सदस्य ने मुख्यमंत्री को भेजा शिकायती पत्र

» एडीए का गजब खेल, खतौनी किसी की मानचित्र किसी के नाम



शिकायतकर्ता मुकेश श्रीवास्तव



राममंदिर से ऊंचा निर्माण सुरक्षा पर सवाल

नियम स्पष्ट हैं श्रीराम मंदिर से ऊंची कोई भी इमारत नहीं बन सकती। लेकिन 'उडुपी टू मुंबई' होटल के ऊंचे तलों ने न सिर्फ इस नियम की धज्जियां उड़ाईं, बल्कि मंदिर सुरक्षा व्यवस्था को भी चुनौती दी है।

कल्पना कीजिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़, मुख्य द्वार के सामने ऊंची इमारतों, और वहां से किसी सद्विधि गतिविधि का अंजाम..

शिकायतों के बावजूद जिला



प्रशासन और विकास प्राधिकरण के अधिकारी खामोश हैं। कारण साफ है होटल मालिक का दबाव और प्रभाव। फाइलें थमी हैं, जांचें सोई हुई हैं, और अवैध इमारतों के सामने शासन-प्रशासन नतमस्तक।

अयोध्या में हर पर्व, हर आयोजन में लाखों श्रद्धालु आते हैं। भीड़, अवैध निर्माण और बिना निकासी-पार्किंग की स्थिति भविष्य के किसी बड़े हादसे की भूमिका लिख रही है।

मुकेश श्रीवास्तव ने चेताया है यदि इस अवैध होटल साम्राज्य पर कार्रवाई नहीं हुई, तो मामला

माननीय उच्च न्यायालय तक जाएगा। सवाल यह है कि क्या श्रीराम जन्मभूमि की पवित्र भूमि पर इस तरह का भ्रष्टाचार चलता रहेगा? क्या रामराज्य की धरती पर भ्रष्टाचारराज कायम रहेगा?

स्वराज इंडिया का सवाल

-क्या अयोध्या विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन की मिलीभगत से राममंदिर के सामने अवैध होटल खड़ा हुआ? और अगर हाँ-तो इस पवित्र भूमि पर अगली इमारत किस कीमत पर उठेगी धन की या श्रद्धा की?

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की पावन जन्मभूमि के ठीक सामने, रामपथ रोड पर दो आलीशान होटल उडुपी टू मुंबई और उडुपी एक्सप्रेस आज पूरे सिस्टम की सड़ांध का प्रतीक बन चुके हैं। इन होटलों का निर्माण जिस जमीन पर हुआ, उसकी कहानी जमीन से नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की गहराइयों से शुरू होती है।

शिकायतकर्ता मुकेश श्रीवास्तव, सदस्य उत्तर प्रदेश खेत मजदूर संगठन, ने मुख्यमंत्री को भेजे अपने पत्र में गंभीर आरोप लगाए हैं कि दोनों होटलों

के लिए अयोध्या विकास प्राधिकरण ने मानचित्र किसी और के नाम पर, जबकि जमीन किसी दूसरे व्यक्ति की खतौनी पर स्वीकृत कर दिया।

यानी, जिस जमीन की मालकी नहीं थी, उस पर होटल निर्माण की इजाजत दे दी गई और ये सब कुछ जेबें गर्म करने के बाद हुआ। श्रीराम मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने स्थित ये होटल बिना पार्किंग के बनाए गए हैं। नतीजा हर दिन सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें, फुटपाथ पर कब्जा और जाम का स्थायी ठिकाना। भक्ति मार्ग पर यह अराजकता केवल असुविधा नहीं, बल्कि सुरक्षा का भी बड़ा खतरा बन चुकी है।

अखिलेश की आजम से मुलाकात महज वोट बढ़ाने की नौटंकी

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अयोध्या आगमन पर उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया और उनके साथ कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में सुरेश खन्ना ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की आजम खान से मुलाकात सिर्फ और सिर्फ वोट बढ़ाने की नौटंकी है।

जब आजम खान 23 महीने तक जेल में बंद थे, तब अखिलेश यादव ने उनके लिए न कोई आवाज उठाई, न कोई चिंता जताई। अब चुनावी माहौल में वे अचानक हमदर्दी दिखा रहे हैं, जो पूरी तरह बनावटी है।

खन्ना ने कहा कि आजम खान के जेल से बाहर आने के बाद जिस तरह के तंज उन्होंने

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वागत करने पहुंचे सुरेश खन्ना



सपा नेतृत्व पर कसे, उससे दोनों के बीच नाराजगी किसी से छिपी नहीं है। अखिलेश यादव को डर है कि कहीं आजम खान, शिवपाल यादव से मिलकर कोई नया गठबंधन न खड़ा कर दें। इसीलिए वे अब सियासी

समीकरण साधने में जुटे हैं। कानून अपना काम करेगा आजम खान के फंसाए जाने के सवाल पर सुरेश खन्ना ने कहा कि जहां जैसी आवश्यकता होगी, वहां कानून अपना काम करेगा। सरकार न्याय की



प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करती। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने कहा कि वहां की जनता का रुझान स्पष्ट है एनडीए पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन की

तैयारियों पर बोलते हुए सुरेश खन्ना ने कहा, आज जो कुछ भी हम अयोध्या में देख रहे हैं, वह प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और संकल्प का ही परिणाम है। श्रीराम नगरी विश्व के केंद्र में पुनः स्थापित हो रही है।





झांसी: 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में योगी ने दी मिनी स्टेडियम की सौगात

कहा- खेलों में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सरकार देगी नौकरी

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

झांसी। झांसी के मानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आयोजित 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह में मंच से योगी आदित्यनाथ ने खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती देने की बात कही है। उन्होंने कहा यूपी का जो भी खिलाड़ी खेल में पदक जीत कर लायेगा उसे सरकार सीधी नौकरी देगी।

बृहस्पतिवार को झांसी में मानी देवी गोयल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्या भारती की ओर से आयोजित 36वें क्षेत्रीय खेलकूद समारोह के समापन अवसर पर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वह समय खत्म हो गया जब लोग कहते थे कि खेलने-कूदने से



समय खराब होता है। आज नया दौर है। खेलकूद में अच्छा प्रदर्शन करने वाले अपना जीवन सजा एवं संवार सकते हैं। कहा, खेल निखारने में खर्च होने वाले पैसा एवं परिश्रम यूपी सरकार व्यर्थ नहीं जाने देगी। यूपी का जो

खिलाड़ी पदक जीतेगा सरकार उसे सीधी भर्ती के जरिए नौकरी देगी। डिप्टी एसपी, कानूनगो, खेल अधिकारी पद सीधे खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सरकार की ओर से अंतर राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं

को दिए जाने वाली पुरस्कार राशि का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी सरकार अपने खिलाड़ियों की हर संभव मदद करेगी। महारानी लक्ष्मी बाई के शौर्य के साथ ही मशहूर हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को याद करते

हुए युवकों को विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में योगदान देने की बात कही। कार्यक्रम में उन्होंने क्षेत्रीय खेलकूद स्वरों के विजेताओं को सम्मानित भी किया। साथ ही सीएम ने मानी देवी गोयल इंटर कॉलेज में मिनी स्टेडियम बनाने की घोषणा भी की।

पहले बीमारू राज्य था यूपी

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश की गिनती बीमारू राज्य के तौर पर थी। यहां के लोग जब बाहर जाते थे तब उनको बाहर कर दिया जाता था। अलग-अलग माफिया प्रदेश में सौदेबाजी करते थे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य नहीं है। मोदी के नेतृत्व में इसके परिणाम सबको दिखाई दे रहे हैं। अब प्रदेश देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। जल्द ही देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया जाएगा।

दंगाई और माफिया थे हावी

सीएम ने कहा कि पिछली सरकारों में दंगाई और माफिया हावी थे माफिया सौदेबाजी करते थे आज तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। सीएम ने कहा कि जब 1947 में भारत आजाद हुआ था, उसके बाद से खुद को सेक्युलर दिखने की होड़ सी मच गई। भारत के मूल्यों को गाली देने वाले खुद को सेक्युलर कहने लगे। ऐसे लोगों का मंचों पर सम्मान भी किया गया।

अखिलेश यादव के निशाने पर बरेली के डीएम अविनाश सिंह

बोले- भाजपा को लाभ दे रहे, राजनीति का इतना शौक है तो चुनाव लड़ लें

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

लखनऊ। बरेली में बवाल और उसके बाद से हो रही प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के निशाने पर डीएम अविनाश सिंह आ गए हैं। अखिलेश यादव ने गुरुवार को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फेंस करते हुए बरेली के बवाल के लिए सीधे डीएम को दोषी करार दिया। यहां तक कहा कि राजनीति का इतना ही शौक है तो चुनाव लड़ लें। कहा कि शासन-प्रशासन ने मिलकर बरेली में बवाल कराया है। अखिलेश यादव ने कहा कि वहां निर्दोषों पर कार्रवाई हो रही है। खोज-खोजकर सपा के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि हालत यह हो गई है कि देश के मुख्य न्यायाधीश को विदेश में बुलडोजर एक्शन पर बोलना पड़ रहा है।

अखिलेश यादव ने कहा कि इनकी



कोशिश की थी हम बरेली न जा पाएं। बरेली में हम उतर ही न पाएं और रामपुर तक भी न पहुंच पाएं। कितनी बार रोकने की कोशिश हुई। कई दौर की बातचीत के बाद रास्ता निकला है। अखिलेश ने कहा कि बरेली में जो कुछ हुआ है वह सरकार और प्रशासन का फेल्योर है। जब पहले से प्लान है कि ज्ञापन देना है तो कैसे यह सब हो गया। प्रशासन ने जानबूझकर यह कराया है। बरेली के जिलाधिकारी अविनाश सिंह पर सीधा हमला



करते हुए कहा कि यह वही लोग हैं जो जिले-जिले में रहकर भाजपा को राजनीतिक लाभ दे रहे हैं। अगर इन्हें इतना ही शौक है तो क्यों नहीं चुनाव लड़ते। अखिलेश ने कहा कि इन्होंने अंबेडकर नगर में कटेहरी विधानसभा चुनाव हमें हराया। कटेहरी में भाजपा को जिताने का इन्हें इनाम मिला है। अंबेडकर नगर छोटा जिला था। बरेली जैसे बड़े जिले का डीएम बनाकर इनाम दिया गया है।

सीतापुर में घर के अंदर चल रही थी पटाखा फैक्ट्री

ढाई कुंतल बारूद और 1.37 सुतली बम बरामद

» विशेष संवाददाता, स्वराज इंडिया ब्यूरो।

सीतापुर। यूपी के सीतापुर में मछरेहटा स्थित घर में पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर ढाई कुंतल विस्फोटक सामग्री बरामद कर संचालक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं नैमिषारण्य पुलिस ने छापेमारी कर 1.37 कुंतल सुतली बम व 18 किलो ग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। साथ ही पुलिस अवैध रूप से पटाखा बेचने और बनाने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह के मुताबिक मछरेहटा के सूरजपुर स्थित नसीर के घर में अवैध रूप से पटाखा बनाने व बेचने की सूचना मिली। सूचना पर बुधवार देर रात पुलिस टीम ने छापेमारी की।

पुलिस टीम को मौके से ढाई कुंतल विस्फोटक सामग्री व पटाखे बरामद हुए। साथ ही कोयला मिक्स पाउडर, रंगीन महताब पटाखे, खाली खोखे, पटाखा जलाने की



बाती, सुतली आदि सामग्री बरामद की। पुलिस को देखते ही नसीर भागने लगा। जिसे दौड़ाकर पकड़ लिया गया। पूछताछ में वह पटाखे बनाने व बेचने का लाइसेंस भी नहीं दिखा सका। आरोपी नसीर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वहीं, नैमिषारण्य पुलिस ने कर्मपुर तिराहे से औरंगाबाद निवासी मेराज को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मेराज के कब्जे से 1.37 कुंतल सुतली बम व 18 किलो ग्राम विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है।